priority basis outside their respective State/Constituencies take longer than 30 days;

(b) if so, the telecommunication cir cle-wise details of recommendations made by MPs upto 31st JanaiTry, 1996 and which still remain unexecuted as on date;

(c) whether any effort has been made/ contemplated to give effect to these re-commendations speedily? and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Sanctions for telephone connection are issued immediately on receipt of instructions from the Hon'ble M.Ps. and normally telephone connections are provided within 30 days, However, for a few cases, it takes more than the prescribed time due to technical non-feasibility/non compliance of formalities by the beneficiaries.

(b) the information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) and (d) Yes, Sir, For speedy provision of the telephones recommended by the Hon'ble M.Ps, for a place outside their constituency, instructions have already been issued whereby the Head of concerned circles would liaise with their counter part for provisions of thelephone connection within 30 days. Wherever, it is technically non-feasible the Head of circle will intimated to the M.P. as well as the beneficiary, the expected date of installation.

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को आपातकालीन वीज़ा

239. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को प्राथमिकता आधार पर और किसी पूर्व सत्यापन के बिना आपातकालीन वीजा जारी करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा; यदि हां, तो किस हद तक;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ङ) जो पकिस्तानी राष्ट्रीक भारत में पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत आकस्मिक संकट के कारण भारत आना चाहते हैं उनको तत्काल वीजा जारी किया जाता हैं। सभी मामलों की तरह इन मामलों में भी वीजा प्रदान करते समय निर्धारित नियमों एवं प्रकियाओं में दिए गए दिशा- निर्देशों का पालन किया जाता हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा देते समय. सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो।

भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिक

240. **श्रीमती सुषमा स्वराज**:

श्री राम जेठमलानी :

श्री राजनाथ सिंह :

श्रीमती मालती शर्मा

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1996 के साप्ताहिक"सन्डे ओब्जरवर" "में ओवर 50,000 पाक नेशनल्ज हाइडिंग इन इण्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि पिछले कुछ वर्षो से भारी संख्या में विदेशी राष्ट्रिक इस देश में अवैध रूप से आते हैं ;

(ग) देश में अवैध रूप से यह रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की अनुमनित संख्या कितनी हैं ;

(घ) ये विदेशी राष्ट्रिक किन – किन देशों के रहने वाले हैं; और

(ङ) सरकार ने इन विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देशों में वापस भेजने के लिये क्या नीति अपनाने का निर्णय लिया हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल,. भाटिया) : (क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही हैं ओर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Steps to contain insurgency in Assam

241. SHRI PAR AG CHALIHA: will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of steps taken/initiated/ contemplated by the Central Government in containing/eradicating insurgency in Assam in particular and North-East region in General during the preceeding three years; and

(b) the policy of the Central Government towards separatist movements raising their heads in the regions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SYED SIBTEY RAZI): (a) the insurgency situation in Assam and the North-East region has been kept under constant watch and close review. Steps taken/initiated for containing/eradicating insurgency in the region during the last three years include the deployment of the Army and the Central Para Military Forces; the most seriously effected areas being notified as "disturbed areas", some secessionist extremist/militant groups being banned and the strengthening and upgradation of the intelligence machinery. Stepped up assistance has been provided for the modernisation of the State Police machinery in the region. Steps to strengthen the local police/State Armed Police Force include training at State Police Training Centres, as also at the North-East Police Academy (NEPA), at Barapani (Meghalaya). The situation is reviewed regularly at various levels to effect co-ordinated action. Simultaneously, steps continue to be taken for promoting accelerated economic development, particularly with a view to improving the basic infrastructure in the region in sectors such as Power and Communications and for generating employment opportunities. Additionally, local youth have been recruited into the Central Para Military Forces and the State Police.

(b) the policy of the Government has been, on the one hand to deal firmly with those indulging in violent activities, and on the other to encourage them to join the national mainstrem. Within this framework, various Accords and Memoranda of Understanding have been signed for implementation with a view to meet the aspirations of the local people and ethnic groups. Further, many underground elements have, as a result of the adoption of above policy and process, come overground and laid down their arms. There have been various measures for the rehabilitation of such elements.

पुरूलिया में हथियार गिराये जाने की घटना

242.**श्री राघवजी**:

श्री सुशी ल कुमार संभाजीराव इन्दें:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन माह के दौरान भारत में पुरूलिया क्षेत्र में विदेशी हथियार गिराये गये थे :

(ख) यदि हां, तो ये हथियार किस देश के हैं और इन हथियारों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार ने हथियार गिराये जाने के मामले में शमिल व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की हैं; और

(घ) इन हथियारों के गिराये जाने का उद्देश्य क्या हैं और इस घटना के पीछे किसी अंतराष्ट्रीय एजेंसी का हाथ पाया गया हैं?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी हां. श्रीमान्

(ख) 16.2.1996 की स्थिति के अनुसार बरामद किए गए हथियारों, गोली बारूद और अन्य वस्तुओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं। हाथियार और गोलीबारूद जिस देश के हैं, उस देश कि नाम का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों जांच - पड़ताल कर रहा हैं।